<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

यमुनानगर, 01 अक्टूबर, 2017

दादूपुर नलवी नहर रद्द करना है उत्तरी हरियाणा के किसानों से धोखा

खट्टर सरकार से लड़ेंगे निर्णायक 'न्याययुद्ध'

कांग्रेस सरकार बनने पर बहाल करेंगे दादूपुर नलवी नहर परियोजना

दादूपुर नलवी नहर परियोजना उत्तरी हरियाणा की जीवनरेखा है और कांग्रेस सरकार बनने पर इसे बहाल कर जल्द पूरा करवाया जाएगा। भाजपा सरकार किसानों से धोखा कर रही है व अब मिलकर खट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने हेतु निर्णायक न्याययुद्ध वक्त की मांग है। यह घोषणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज यमुनानगर में हरियाणा किसान खेत मजदूर कांग्रेस–हरियाणा कृषक समाज–भारतीय किसान यूनियन के एक विशाल 'न्यायप्रदर्शन व धरने' को संबोधित करते हुए की।

विरोध प्रदर्शन में कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अंबाला जिले से आए हजारों किसानों ने भाग लेकर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा दादूपुर नलवी नहर परियोजना को रद्द करने के फैसले का कड़ा विरोध जताया। श्री सुरजेवाला के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के अनेक पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और नेताओं ने भाग लिया।

41 दिन से धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के नेताओं, श्री हरपाल सिंह, राजेश दहिया, बाबूराम, सुखवीर, अर्जुन व अन्य नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने इसमें आगे बढ़ शिरकत की।

विरोध प्रदर्शन में किसान की हुंकार को बुलंद करते हुए श्री सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश के किसान खट्टर सरकार के इस किसान विरोधी विश्वासघात का जमकर जवाब देंगे और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस तुगलकी फैसले से अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिलों के 225 गांवों की लगभग एक लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई से वंचित होना पड़ेगा। खट्टर सरकार ने फिर साबित किया है कि उसका गरीबों और किसानों के हितों से कोई सरोकार नहीं।

आंदोलित व आक्रोशित प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए श्री सुरजेवाला ने बताया कि दादूपुर नलवी नहर परियोजना सन 1985 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा शुरु की गई थी। अक्टूबर, 2005 में कांग्रेस ने ही एक बार फिर से इस योजना को चालू किया और किसानों को नहरी पानी उपलब्ध करवाने व भूजल स्तर उठाने के लिए शाहबाद फीडर, शाहबाद डिस्ट्रीब्यूटरी और नलवी डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए 1019 एकड़ जमीन को अधिग्रहित किया। जमीन अधिग्रहण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक लगभग 200 करोड़ रु. का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा सिंचाई विभाग द्वारा इन नहरों को बनाने में 111 करोड़ 17 लाख रु. खर्च किए जा चुके हैं। 300 करोड़ रु. से ज्यादा खर्च करने के बाद उत्तरी हरियाणा के गिरते भूजल स्तर को नया जीवनदान देने वाली इस परियोजना को रद्द करके खट्टर सरकार ने लाखों किसान परिवारों पर कुठाराघात किया है। हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार हरियाणा में बगैर समझ व बगैर जानकारी के तुगलकी फैसले लेने बारे बदनाम है। क्या मुख्यमंत्री व सरकार इस बात को समझ पाए हैं कि

लगभग 58 फुट चौड़ी व 30 फुट गहरी इस नहर को पाटने में किसान को प्रति एकड़ लगभग 40 लाख रु. का खर्चा आएगा, जो भूमि की कीमत के बराबर है। इसके अलावा भाजपा सरकार किसान से पूरी मुआवजा राशि, 15 प्रतिशत ब्याज सहित लेने की तैयारी में है। इसे देने के लिए किसान को या तो अपनी बाकी की जमीन बेचनी पड़ेगी या फिर सरकार उसकी संपत्ति की कुर्की कर लेगी। दुर्भाग्य से सरकार को यह भी मालूम नहीं कि अधिग्रहण की गई भूमि पर 10 किलोमीटर से अधिक तो सड़क बन चुकी व राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल भी बन चुके। तो क्या अब सरकार इन सड़कों को नए सिरे से उखाड़ेगी, ताजा बने हुए पुलों को तोड़ डालेगी व राष्ट्रीय राजमार्ग की अलाईनमेंट को नए सिरे से बदल डालेगी? मुख्यमंत्री खट्टर तो यह भी भूल गए कि सरस्वती नदी में पानी न मिलने पर दादूपुर नलवी का पानी ऊंचा चांदना गांव में सरस्वती नदी में छोड़ मौजूदा सरकार द्वारा खानापूर्ति की गई है। ऐसे में दादूपुर नलवी नहर के साथ साथ सरस्वती प्रोजेक्ट भी अपने आप बंद हो जाएगा।

हरियाणा के किसानों को फसल के दाम न मिलने का हवाला देते हुए श्री सुरजेवाला ने कहा कि 'धान का कटोरा' कहे जाने वाले हरियाणा में धान की फसल भाजपाई शोषण के चलते औने–पौने दामों पर पिट रही है। 25 प्रतिशत धान की फसल मंडियों में बिक चुकी पर आज तक सरकारी खरीद शुरु नहीं हुई। पीआर धान का एमएसपी 1590 रु. प्रति क्विंटल है, पर वह 1400 रु. प्रति क्विंटल बिक रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि करनाल–कुरुक्षेत्र–शाहबाद–अंबाला का किसान आलू व टमाटर की फसलें 2 रु. किलो से भी कम की बिकवाली के विरोध में सड़कों पर उतरा तो खट्टर सरकार ने उन पर लाठियां भांजी। यही हाल पापुलर व सफेदे की लकड़ी का हुआ, जिसके दाम 1200–1400 रु. प्रति क्विंटल से गिरकर, 600–800 रु. प्रति क्विंटल तक आ गए और किसान की रोजी रोटी लुट गई।

विरोध प्रदर्शन में शाहबाद के पूर्व विधायक, श्री अनिल धंतोड़ी व यमुनानगर से किसान कांग्रेस अध्यक्ष, श्री सतीश सांगवान तथा अग्रणी किसान नेता, श्री बलविंदर संधाय ने हजारों किसानों सहित आगे बढ़ संघर्ष का बिगुल और तेज करने का वायदा तथा आह्वान किया।

विरोध प्रदर्शन को पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य, पूर्व विधायक रमेश गुप्ता, पूर्व विधायक फूल सिंह खेड़ी, पूर्व विधायक श्री पवन दीवान, पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्य क्ष सुमित्रा चौहान, प्रदेश कांग्रेस महासचिव, श्री वीरेंद्र राठौर, श्री संजय छोकर, श्री सुरेश यूनिसपुर व श्री नाहर सिंह संधू व रमेश चौधरी व श्री सतबीर भाणा, हरियाणा किसान खेत मजदूर किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र फोगाट, हरियाणा कृषक समाज के अध्यक्ष ईश्वर दनौदा, परमजीत राणा, रुद्र प्रताप, सचिन, महावीर गुर्जर, श्रीमति ऊषा कमल, राकेश सडौरा, गोविंद सडौरा, लकी रादौर, नरेश वाल्मीकि, शिवचरण, नरेंद्रपाल मोंटी, राजेश चौधरी, रंजीता मेहता, रणधीर राणा, अमन चीमा, वीरेंद्र जागलान, सुरेश रोड़ आदि ने भी संबोधित किया।